

सचिन पायलट होंगे कांग्रेस का नया ओबीसी चेहरा

राहुल गांधी ने यह सोचा समझा निर्णय लिया, जातिगत जनगणना के निर्णय के बाद। इस निर्णय से बैकवर्ड, दलित व आदिवासी देश की राजनीति में अब पूरी तरह से सैंटर स्टेज पर आ गये हैं

**-रेणु मिश्र-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-**
नई दिल्ली, 2 मई। सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी का नया ओबीसी चेहरा हैं। राहुल गांधी ने बहुत सोच-विचार कर उन्हें, खासतौर से जातिगत जनगणना के संदर्भ में, पार्टी के नये ओबीसी चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट करने का निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि जातिगत सर्वे ने पिछड़ों, दलितों तथा आदिवासियों के मुद्दे को राष्ट्रीय राजनीति के केन्द्र में पहुँचा दिया है।

आज शाम कांग्रेस वर्किंग कमेटी (सीडब्ल्यूसी) की मीटिंग के बाद, सचिन पायलट और भूपेश बघेल को प्रैस कॉन्फ्रेंस के लिये उतारा गया। ये दोनों ही ओबीसी हैं। लेकिन चूँकि भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इसलिये वे ईडी की नजर में हैं तथा उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप भी हैं। बघेल का समय गुजर चुका है।

सचिन पायलट युवा और करिश्माई नेता हैं। वे स्वच्छ छवि के मालिक हैं तथा युवा एवं महिलाएं उनकी जबरदस्त प्रशंसक एवं समर्थक हैं। उनकी लोकप्रियता केवल राजस्थान में ही नहीं,

■ सी.डब्ल्यू.सी. की बैठक के बाद, शाम को सचिन पायलट व भूपेश बघेल को प्रैस कॉन्फ्रेंस में संबोधित करने के लिये उतारा कांग्रेस हाईकमान ने।

■ दोनों, नेता ओबीसी हैं। बघेल हालांकि वजनी हैं, क्योंकि, मु.मंत्री रह चुके हैं, परन्तु उन पर ईडी का शिकंजा कसा हुआ है तथा भ्रष्टाचार के आरोप हैं।

■ अतः बघेल बीता हुआ, “पास्ट” (इतिहास) हैं। पर, पायलट युवा हैं, करिश्माई हैं तथा साफ व स्वच्छ छवि के नेता हैं, जिनकी युवाओं में, महिलाओं में, अच्छी लोकप्रियता है, केवल राजस्थान में ही नहीं, पर, उत्तर भारत के कई अन्य राज्यों में भी।

■ राहुल गांधी लगातार “जातिगत जनगणना” की बात कर रहे थे तथा ओबीसी, दलित व आदिवासी को पुनः कांग्रेस में लाने के लिये जातिगत नेताओं (कास्ट लीडर्स) को प्रोजैक्ट करने की जरूरत को पहचान रहे हैं।

अपितु पूरे उत्तर भारत में है।

अगर कांग्रेस नेतृत्व ने सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने के लिये जोर लगाया होता, तो वे किसी भी पार्टी के प्रथम गुर्जर मुख्यमंत्री के रूप में सामने आये होते और कांग्रेस

को उत्तर भारत में इसका बहुत बड़ा फायदा मिला होता, क्योंकि विधानसभा क्षेत्रों की बहुत बड़ी संख्या में गुर्जर मतदाताओं का दबदबा है। वादे करना एक चीज है, किन्तु जाति-आधारित एजेंडे को वास्तव में और सही रूप में

कार्यान्वित करना बिल्कुल भिन्न चीज है।

चूँकि राहुल गांधी जातिगत जनगणना के महत्व और आवश्यकता के बारे में, तथा ओबीसी, दलितों और आदिवासियों को कांग्रेस में वापस लाने की जरूरत के बारे में निरन्तर बात करते आ रहे हैं, इसलिये उन्होंने पिछड़ी जातियों के नेताओं को प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया है। अपेक्षानुरूप, सीडब्ल्यूसी मीटिंग मूलतः दो बिन्दुओं पर केंद्रित थी: पहलगाम हमला, जिसके विषय में एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री से कहा गया कि वे पाकिस्तान तथा उसके द्वारा पोषित आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करें। दूसरा बिन्दु जातिगत जनगणना थी, जिसके बारे में सरकार ने जो घोषणा की है, उससे कहीं बहुत ज्यादा कांग्रेस चाहती है।

कांग्रेस को आशंका है कि मोदी सरकार के अन्य जुमलों की तरह, जातिगत जनगणना भी कहीं एक जुमला बनकर न रह जाये। सीडब्ल्यूसी ने जो देकर कहा कि जातिगत सर्वे सही रूप में कार्यान्वित हो, जिससे यह सामाजिक सशक्तीकरण एवं परिवर्तन का एक प्रभावी उपाय बन सके।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के टेंडरों की जाँच के लिये आठ सप्ताह का समय

जयपुर, 2 मई। राजस्थान हाईकोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से बीते पाँच साल में दिए पाँच सौ टेंडरों में भ्रष्टाचार की जाँच को लेकर जाँच एजेंसी को आठ सप्ताह का समय दिया है। जस्टिस उमाशंकर व्यास की एकलपीठ ने यह आदेश टीएन शर्मा की याचिका

■ विभाग के पाँच साल के पाँच सौ टेंडरों की जाँच के लिये गठित एसआईटी ने जाँच के लिये हाई कोर्ट से अतिरिक्त समय मांगा।

पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील सिहाग अदालत में हाजिर हुए। उन्होंने अदालत में तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश कर कहा कि (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

महेश जोशी को 8 से 11 मई की अंतरिम जमानत मिली

जयपुर, 2 मई। ईडी मामलों की विशेष कोर्ट ने शुक्रवार को जल जीवन मिशन के करीब 900 करोड़ रुपए घोटाले से जुड़े मामले में पूर्व मंत्री महेश जोशी को, उनकी पत्नी के निधन के चलते, 8 से 11 मई तक अंतरिम जमानत का लाभ दिया है। जोशी को अंतरिम जमानत अवधि खत्म होने पर 11 मई को सुबह 8 बजे जेल में सरेंडर करना होगा। इससे पहले ईडी कोर्ट ने जोशी को गत 28 अप्रैल को पत्नी के अंतिम क्रिया- कर्म व धार्मिक रिवाजों के निर्वाह के लिए 4 दिन की अंतरिम

■ महेश जोशी के अधिवक्ता ने पत्नी के निधन के संबंध में रीति-रिवाजों के लिये अंतरिम जमानत 9 दिन बढ़ाने की मांग की थी।

जमानत दी थी। इस अंतरिम जमानत अवधि को बढ़ाने के लिए जोशी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने गुरुवार को दोनों पक्षों की बहस सुनकर फैसला शुक्रवार पर रखा था। वहीं, अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने पर गुरुवार शाम को जोशी ने जेल में सरेंडर कर दिया था।

प्रार्थना पत्र में अधिवक्ता दीपक चौहान ने कहा कि महेश जोशी को उनकी पत्नी के निधन के बाद के रीति रिवाजों में हिस्सा लेना है। वे 71 साल के हैं और पत्नी के निधन के बाद (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

गिरते पड़ते, किसी भी तरह शशि थरुर पहुँच ही गये, एयरपोर्ट प्र.मंत्री को “रिसीव” करने

इससे प्र.मंत्री मोदी को मौका मिल गया, कांग्रेस पर कटाक्ष करने का कि थरुर के इस कठिन प्रयास से कई नेताओं की नींद उड़ जायेगी

**-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-**
नई दिल्ली, 2 मई। तिरुवन्तपुरम लोकसभा सांसद शशि थरुर, जो हमेशा घूमते रहते है, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, जो गुरुवार रात केरल की राजधानी पहुँचे थे, के आगमन पर स्वागत के लिये ठीक समय पर पहुँच ही गये थे और इससे प्रधानमंत्री को थरुर की कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष करने का अवसर मिल गया।

मोदी ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुये कहा कि कांग्रेस सांसद शशि थरुर की यहाँ विजिंजम इंटरनेशनल सीपोर्ट पर मौजूदगी से बहुत से लोगों की “रातों की नींद उड़ गई होगी।”

थरुर की वहाँ मौजूदगी पर मोदी की सीधी टिप्पणी ऐसे समय हुई है, तिरुवन्तपुरम के कांग्रेस सांसद (थरुर) पर उन्हीं की पार्टी के उनके साथी यह आरोप लगा रहे हैं कि पहलगाम आतंकी हमले पर थरुर भाजपा के प्रति नरम रख अपना रहे हैं।

थरुर ने सोशल मीडिया पर बताया कि वे किस तरह एयरपोर्ट पहुँचे। उन्होंने

■ मोदी का कटाक्ष इसलिए मायने रखता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के ही कई नेता, आजकल थरुर पर आरोप लगा रहे हैं कि थरुर पहलगाम के आतंकवादी हमले के बाद से भाजपा के प्रति अधिक नरम हो गये हैं, उतने आक्रामक नहीं रहे।

“एक्स” पर लिखा, “दिल्ली एयरपोर्ट पर विलम्ब हो जाने के बावजूद, मेरे लोकसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आगमन पर, उनके स्वागत के लिये मैं किसी तरह तिरुवन्तपुरम समय पर पहुँच ही गया। विजिन्जम पोर्ट, जिस प्रोजेक्ट से शुरू से ही जुड़े होने का मुझे गर्व है, को उनके द्वारा विधिवत रूप से लोकार्पित किये जाने की मुझे उत्सुकतापूर्ण प्रतीक्षा थी।”

प्रधानमंत्री मोदी की 2025 में यह पहली केरल यात्रा है और यहाँ एक बहुत बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजैक्ट को लोकार्पित करने आये हैं, जो केरल ही नहीं, पूरे देश के स्वरूप को बदल देगा। शशि थरुर 2009 से निरन्तर तिरुवन्तपुरम लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं और

विजिंजम तो उनके मन में बसता है। केरल की राजधानी की अभूतपूर्व रूप से सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच, प्रधानमंत्री तिरुवन्तपुरम अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे। विजिन्जम इंटरनेशनल डीपवॉटर मल्टीपरवज सीपोर्ट को राष्ट्र को समर्पित करने केरल की राजधानी में आये। यह 8900 करोड़ रूपए की लागत से तैयार हुआ है।

यह देश का प्रथम कन्टेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, जो भारत के समुद्री क्षेत्र में, “विकसित भारत” के स्वप्न के हिस्से के रूप में, क्रांतिकारी तरक्की का प्रतिनिधित्व करता है।

सामरिक महत्व वाले विजिन्जम पोर्ट की पहचान अत्यधिक प्राथमिकता (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

असुरक्षित होटलों के संचालन पर रोक लगायें

राज्य मानवाधिकार आयोग ने अजमेर होटल अग्निकांड पर दिशा निर्देश दिये

जयपुर, 2 मई। राज्य मानवाधिकार आयोग ने अजमेर के होटल में हुए अग्निकांड के बाद ऐसे असुरक्षित होटलों को बंद करने की मंशा जताई है। आयोग ने कहा कि अजमेर में रोजाना हजारों पर्यटक आते हैं। ऐसे में जरूरी है कि जिला प्रशासन और नगर निगम सभी सरायों और होटलों की सूची बनाकर, उन्हें असुरक्षित पाए जाने पर, उनके संचालन पर रोक लगाए। इसके साथ ही, इन होटलों में फायर एनओसी की अनिवार्यता को लागू करें, ताकि यहां ठहरने वालों के साथ अग्निकांड जैसी जानलेवा घटना न हो। वहीं, आयोग ने अजमेर कलेक्टर, एसपी और निगम आयुक्त को कहा है कि शहर की सभी होटलों की सूची बनाकर उनकी सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति को कन्फर्म कर

■ आयोग ने अजमेर कलैक्टर, एसपी तथा निगम आयुक्त को अजमेर के होटलों की सूची बनाकर सुरक्षा व्यवस्था की कन्फर्म रिपोर्ट पेश करने को कहा।

इसकी रिपोर्ट आयोग में पेश की जाये और अग्निकांड में पीड़ितों को क्षतिपूर्ति राशि देना सुनिश्चित किया जाये। आयोग अध्यक्ष जस्टिस जीआर मूलचंदानी ने यह आदेश मामले में प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट्स पर दिए।

आयोग ने कहा कि अग्निकांड में जले होटल के मालिक ने स्थानीय प्रशासन से बिना फायर एनओसी लिए होटल संचालित की, जिसके चलते आग लगने से चार लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। आग की लपटें देखकर होटल कर्मचारी भाग गए और

एक महिला को अपने बच्चे को बचाने के लिए होटल से नीचे फेंकना पड़ा। आयोग ने कहा कि शहर के कई आवासीय भवनों को होटलों में तब्दील किया जा चुका है और विभागों की स्वीकृति और एनओसी के बिना इनका संचालन किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि स्थानीय प्रशासन की ओर से इस आवश्यक पहलू को नजरअंदाज किया गया है, जिससे दरगाह के आसपास अग्निकांड होने पर फायर ब्रिगेड के पहुंचने और बचाव कार्य में भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

राज्य सरकार व चुनाव आयोग पंचायत चुनाव कार्यक्रम बनाये

जयपुर, 2 मई। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश की 6759 पंचायतों के चुनाव स्थगित कर निवर्तमान सरपंचों को प्रशासक लगाए जाने से जुड़े मामले में राज्य सरकार व चुनाव आयोग से पूछा है कि वे चुनाव कार्यक्रम सहित बताएं

■ हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से 4 फरवरी तथा 25 मार्च 2025 के निर्देशों की पालना करने के लिये भी कहा।

कि पंचायतों के चुनाव कब होंगे। वहीं, राज्य सरकार को इस संबंध में 4 फरवरी 2025 व 25 मार्च 2025 को दिए गए निर्देशों की पालना के लिए कहा है। अदालत ने राज्य चुनाव आयोग से चार सप्ताह में जवाब भी मांगा है। जस्टिस चन्द्रशेखर व जस्टिस आनंद शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश गिराज सिंह देवदा व अन्य की जनहित याचिका पर दिए। अदालत ने मामले की आगामी सुनवाई 30 मई को तय की है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘जातिगत जनगणना में मुसलमानों की जाति/ उपजाति का उल्लेख करना साजिश है’

कई मुसलमान नेताओं का मानना है कि जाति जनगणना में पसमंदा मुसलमानों व अशरफ मुसलमानों आदि से अपनी जाति/उपजाति लिखवाने का प्रावधान मुस्लिम समुदाय को जातियों व उपजातियों में बांटने की सुनियोजित चाल है।

■ इन नेताओं के अनुसार . पूरे मुस्लिम समुदाय ने एकजुट व संगठित होकर वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक का विरोध किया था, अब सरकार जातिगत जनगणना के जरिए मुसलमानों की एकता व एकजुटता को तोड़ना चाहती है।

■ इन मुस्लिम नेताओं के अनुसार, मुसलमानों में पसमंदा (बैकवर्ड) मुसलमान व अशरफ, अपर कास्ट जैसे सैय्यद, पठान, शेख आदि में विभाजन मौजूद है, पर, पूरे मुस्लिम समुदाय के हितों व समाज के “कम्युनिटी वेलफेयर” के कारण विभाजन सदा सुस्त रहते हैं, पर, अब जातिगत जनगणना, इस विभाजन (फॉल्ट लाइन) को और प्रज्वलित करेगी।

उनकी सामूहिक आवाज और सौदेबाजी की शक्ति कमजोर हो सकती है।

इस मुद्दे के मूल में, हाल ही में लागू किए गए वक्फ कानून को लेकर बढ़ता

तनाव है। यह कानून, जिसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को पुनर्गठित और केन्द्रीकृत करना था, को मुस्लिम नेताओं और अन्य लोगों की तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा है। कई लोगों को विपक्ष की एकता पर आश्चर्य हुआ, यहाँ तक कि हिन्दू बहुल विपक्षी दलों ने भी कानून को चुनौती देने के लिए मुस्लिम नेतृत्व के साथ हाथ मिलाया। पर्यवेक्षकों का मानना है कि इस अप्रत्याशित गठबंधन का सामना करने के लिए मोदी सरकार को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ा।

दिल्ली के एक राजनीतिक विश्लेषक, डॉ. इमरान कुरैशी का कहना है, “जाति गणना उतनी अनुकूल नहीं है, जितनी नज़र आती है। धार्मिक संबद्धता

के साथ-साथ जाति की पहचान को अनिवार्य करके, सरकार मुस्लिम समुदाय के अंदर कलह का बीज बोने का प्रयास कर रही है। मुसलमानों में पसमांदा (पिछड़े) मुसलमानों और अशरफ (ऊँची जाति) सय्यद, पठान और शैख के बीच विभाजन वास्तविक है। पर मुस्लिम समाज के हित में इन्हें कभी भी उभारा नहीं गया और यह सर्वे इन दरारों को उभार देगा।

पसमांदा मुस्लिम मूवमेंट, जो पिछड़े व दलित मुसलमानों के अधिकारों के लिए संघर्षरत है, को हाल ही में काफी बल मिला है। खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश के राजनैतिक रणनीतिकार मानते हैं कि मुस्लिम (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नैशनल हैरल्ड केस, सोनिया व राहुल को कोर्ट का नोटिस

नयी दिल्ली, 02 मई। राष्ट्रीय राजधानी में एक विशेष अदालत ने नेशनल हैरल्ड धन शोधन मामले में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोक सभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को शुक्रवार को नोटिस जारी किया।

इससे पहले इसी माह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ

■ नैशनल हैरल्ड केस में राउज एवेन्यू कोर्ट के निर्देश पर न्यायाधीश ने ये नोटिस जारी ? किए हैं।

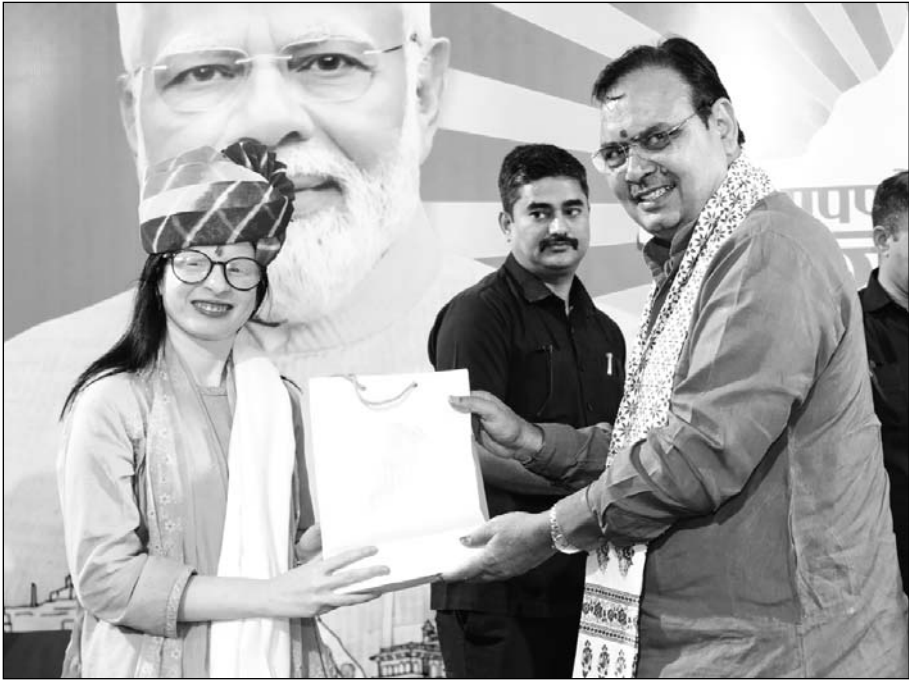
अदालत में कार्यवाई के लिए नयी शिकायत दायर की थी। इसमें संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ धन शोधन निवारक अधिनियम 2002 की धारा 44 और 45 के तहत आरोप लगाये गये हैं।

मामले की सुनवाई कर रहे राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम) ने आरोपियों के खिलाफ नोटिस जारी करने के आदेश जारी किये। यह मामला (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राष्ट्र निर्माण में पब्लिक सर्वेंट की अहम भूमिका : भजनलाल शर्मा

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में राजस्थान के चयनित अभ्यर्थियों का सम्मान कर बधाई दी और विश्वास व्यक्त किया है कि वे सभी अमृत काल के योद्धा के रूप में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में अपना योगदान देंगे तथा उ्कृष्ट लोक सेवा के माध्यम से हमेशा राजस्थान का नाम देशभर में रोशन करेंगे। शर्मा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने पिछले वर्ष से चयनित प्रतिभाओं के सम्मान की पहल की है। देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माने जाने वाली यह परीक्षा पास करके प्रदेश के युवाओं ने अपने माता-पिता के साथ ही क्षेत्र और पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि इस सफलता के बाद जीवन में बेहतर कार्य करते हुए परिजनों की खुशी के भाव को जीवन में आगे भी बनाए रखें।

मुख्यमंत्री ने ‘कर्ता के आगे हारे करता’ उक्ति का उल्लेख करते हुए कहा कि किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है तथा दृढ़ संकल्प के साथ की गई मेहनत से सफलता अवश्य मिलती है। उन्होंने कहा कि इस प्रतिष्ठित परीक्षा में सफलता के बाद भी चयनित युवाओं के जीवन में नए परिश्रम का दौर शुरू होगा। क्योंकि राष्ट्र निर्माण और गरीब



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को उनके निवास पर आयोजित सम्मान समारोह में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में राजस्थान के चयनित अभ्यर्थियों का सम्मान किया।

कल्याण में लोक सेवक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने जीवन में विनम्रता एवं धैर्य को अपनाते हुए आमजन की आकांक्षाओं को पूरा करने का आ न किया।शर्मा ने कहा कि लोक सेवक प्रशासन के कर्णधार हैं तथा लोक सेवा का महत्व हमारे समाज और राष्ट्र के लिए असीमित है। इसलिए लोक

सेवकों का नवाचारी होना महत्वपूर्ण है, ताकि आम लोगों को बेहतर नागरिक-केंद्रित सेवाएं प्रदान की जा सकें। उन्होंने आ न किया कि हमारे प्रदेश की मिट्टी ने हमेशा से वीरों, विद्वानों और कर्मठ लोगों को जन्म दिया है और अब वे सभी भी अपनी सेवा के माध्यम से गौरवमयी मिट्टी की खुशबू को फैलाएं और

कर्मभूमि के साथ ही जन्मभूमि से जुड़े रहे।

समारोह में मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सिविल सेवा में चयनित प्रतिभाओं के सम्मान की इस पहल से प्रदेश के होनहारों को प्रेरणा मिल रही है। उन्होंने कहा कि लोकसेवक के रूप में देश और

भगवान परशुरामजी की शोभायात्रा आज

जयपुर। राजस्थान ब्राह्मण महासभा की ओर से शनिवार को शाम साढ़े पांच बजे जलेब चौक से गाजेबाजे और लवाजमे के साथ भगवान श्री परशुराम की शोभायात्रा निकाली जाएगी। ब्रह्म पीठाधीश्वर रामरतनदास देवाचार्य, शुक् संप्रदायाचार्य अलबेली शरण माधुरी एवं अन्य शोभायात्रा का शुभारंभ करेंगे। मुख्य रथ के आगे 2100 महिलाएं एक ही गणवेश में मंगलगान करते हुए शोभायात्रा की भव्यता में चार चांद लगाएंगी। शोभायात्रा में विभिन्न स्वरूपों की जीवंत एवं स्वचालित 21 झांकियां होंगी।

जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को फैमिली पेंशन के साथ ही दिव्यांग पेंशन का लाभ देने को कहा है।

न्यायमित्र पूर्वी माधुर ने बताया कि याचिकाकर्ता 63 साल की एकल बुजुर्ग महिला है और मानसिक दिव्यांग है। उसके पिता सचिवालय और मां चिकित्सा विभाग में कार्यरत थीं। दोनों का पूर्व में निधन होने पर वह अपने भाई-भाभी के पास रहने लगीं। वहीं कुछ सालों पहले उसकी भाभी का भी निधन हो गया। याचिकाकर्ता ने फैमिली पेंशन के लिए पिता के विभाग में आवेदन किया, लेकिन विभाग ने उसका आवेदन यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उसके पिता ने सरकारी सेवा में रहते हुए कभी भी याचिकाकर्ता की मानसिक दिव्यांगता के बारे में कोई कायूक विभाग ने जुलाई, 2010 को उसे यह पेंशन देने से इनकार कर दिया।

31 जिला संयोजक एवं सह-संयोजक नियुक्त

जयपुर। एक राष्ट्र एक चुनाव अभियान में जन जागरूकता के लिए प्रदेश के 31 जिलों में संयोजक एवं सह संयोजकों की नियुक्ति की है।

अभियान के प्रदेश संयोजक सुनील भार्गव ने बताया कि अभियान के व्यापक प्रचार प्रसार के साथ जन जागरूकता के लिए जिला संयोजकों एवं सह-संयोजकों की नियुक्ति की गई है।

सेचुरेशन कैम्पेन का आयोजन

जयपुर। भारत सरकार के निर्देश पर पीएम-किसान योजना के अंतर्गत राज्य में प्रत्येक ग्राम स्तर पर 1 मई से 31 मई तक 30 दिवसीय सेचुरेशन कैम्पेन का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत योजनान्तर्गत लाभ से वंचित पात्र कुषकों को योजना से जोड़ा जा सकेगा। इन सेचुरेशन कैम्पों में प्रत्येक ग्राम से संबंधित विलेज नोडल अधिकारी नागरिक सेवा केन्द्र के संचालक एवं इण्डिया पोस्ट पेमेन्ट बैंक के समन्वयक उपस्थित रहेंगे। ऐसे कुषक जो कि योजना की पात्रता रखते हैं परन्तु योजनान्तर्गत आवेदन नहीं कर पाए हैं, उनके आवेदन सीएससी केन्द्रों पर सेचुरेशन कैम्पेन के दौरान पूर्ण करवाये जायेंगे।

गंभीर चोट आई और भय का माहौल पैदा हो गया। इसी तरह पूर्व में भी यहां घटनाएं हुई हैं। इसके अलावा मोती ढुंगरी सेटेलाइट अस्पताल में भी बिना जरनेटर बिजली जाने पर टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज करने की खबर प्रकाशित हुई है। इस तरह की भविष्य में घटनाएं नहीं हो, इसलिए मामले में प्रसंज्ञान लेकर एसएमएस अस्पताल और जिला प्रशासन को निर्देश दिए जा रहे हैं।

समय आने पर मैं अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सामने रखूँगा। आशा बैरवा व डॉ. अर्चना शर्मा को न्याय दिलाने के लिये मैं सी.बी.आई. द्वारा जांच कराये जाने के लिये तैयार हूँ। मुझे विश्वास है कि धरना प्रदर्शन के कारण आत्महत्या के उत्तेरण जैसा आरोप न्यायालय में नहीं टिकेगा और ऐसे अनर्गल अनुसंधान नतीजे देने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी कठोर प्रशासनिक कार्यवाही होगी। सत्य की जीत होगी तथा मैं एक बार पुनः निर्दोष साबित होऊँगा।

■ मुख्यमंत्री ने युवा-अधिकारियों से विमर्शता व धैर्य को अपनाने तथा जहाँ से जुड़े रहने का किया आह्वान

समाज की सेवा का सौभाग्य चुनिंदा लोगों को ही मिल पाता है। महानिदेशक पुलिस ने कहा कि अपने सेवाकाल में हमेशा गरीब कल्याण को प्राथमिकता दें और अपनी सफलता में माता-पिता और परिजनों के योगदान को कभी नहीं भूलें।

समारोह में जयपुर निवासी दृष्टिबाधित मनु गर्ग ने मुख्यमंत्री से संवाद करते हुए बताया कि उन्होंने दृष्टिबाधित होने के बावजूद सिविल सेवा परीक्षा में देशभर में 91वां स्थान हासिल किया है। उन्होंने अपनी इस सफलता का मूल मंत्र अपनी माताजी के संकल्प को बताया। वहीं देशभर में 20वां स्थान हासिल करने वाले जोधपुर निवासी त्रिलोक सिंह ने बताया कि लोक सेवक के रूप में वे भारतीय सेना में सेवा दे चुके अपने पिता द्वारा दी गई प्रेरणा को आगे बढ़ाएंगे।

मुख्यमंत्री ने चयनित प्रतिभाओं को शॉल ओढ़ाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। कार्यक्रम के अन्त में मुख्यमंत्री के साथ चयनित युवाओं का सामूहिक फोटो सेशन भी हुआ। इस अवसर पर राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी एवं यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी मौजूद रहे।

दिया कुमारी ने बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान का लोगो और थीम साँन्ग लांच किया

जयपुर। राज्य में बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रयासों के तहत उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने ‘बाल विवाह मुक्त राजस्थान’ अभियान की शुरुआत की है।

उपमुख्यमंत्री द्वारा अभियान का नया लोगो और थीम साँन्ग भी जारी किया गया है। यह लोगो और साँन्ग लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ते हुए बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित

है। जस्टिस विक्रम नाथ व जस्टिस सदीप मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश जारी किया है। अर्चना शर्मा के पति सुनित उपाध्याय की एसएलपी को खारिज करते हुए दिए। हाईकोर्ट ने इस मामले में 20 फरवरी को आदेश जारी कर विधायक गोठवाल के खिलाफ एंडीजे कोर्ट लालसोट, दौसा के 9 फरवरी 2022 के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें उनके खिलाफ आरोप तय किए गए थे। इसके अलावा हाईकोर्ट ने

है। जस्टिस विक्रम नाथ व जस्टिस सदीप मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश जारी किया है। अर्चना शर्मा के पति सुनित उपाध्याय की एसएलपी को खारिज करते हुए दिए। हाईकोर्ट ने इस मामले में 20 फरवरी को आदेश जारी कर विधायक गोठवाल के खिलाफ एंडीजे कोर्ट लालसोट, दौसा के 9 फरवरी 2022 के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें उनके खिलाफ आरोप तय किए गए थे। इसके अलावा हाईकोर्ट ने

सिविल लाइंस कूच करने के प्रयास में बेनीवाल समर्थकों सहित हिरासत में

जयपुर। एसआई भर्ती निरस्त करने और आरपीएससी भंग करने की मांग को लेकर आरएलपी संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने शुक्रवार को पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जालपुरा स्थित आवास से समर्थकों के साथ सिविल लाइंस कूच करने का प्रयास

■ बोले, “एस आई भर्ती रद्द नहीं की, तो एक लाख युवा कूच करेंगे”

किया, लेकिन पुलिस ने कमिश्नरेट के बाहर बैरिकेडिंग पर रोक दिया। इसके बाद वे अपने समर्थकों के साथ सड़क पर धरने पर बैठ गए। बेनीवाल के समर्थकों ने डोल बजाकर सरकार को जगाने का प्रयास किया। एक घंटे बाद पुलिस ने बेनीवाल और उनके समर्थकों को हिरासत में ले लिया और सांगानेर सदर थाने ले गई।

इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि हमने सिविल लाइंस कूच करने का ऐलान किया है। अगर सरकार ने एसआई भर्ती को रद्द करने का फैसला नहीं लिया, तो आने वाले दिनों में प्रदेशभर से एक लाख नौजवान जयपुर आएंगे और रैली कर शहर को जाम कर देंगे। उन्होंने कहा, वे एसआई भर्ती को निरस्त करने, आरपीएससी का पुनर्गठन करने, रीट लेवल-1 और आरएएस भर्ती की जांच करवाने की मांग को लेकर युवा

अंता विधायक मीणा को मिली सजा रद्द करने से इनकार

■ हाईकोर्ट ने तत्काल सरेंडर करने के आदेश दिये

प्रकरण दर्ज थे। अभियुक्त के भय व आतंक के कारण पुलिसकर्मी व लोक सेवक उसके खिलाफ बयान देने की स्थिति में नहीं थे। यहां तक की पुलिस के मौके पर मौजूद होने के बावजूद रिपोर्ट तक नहीं की गई। वहीं अभियुक्त के स्थानीय इलाके में मौजूद होने के बावजूद तीन साल तक उसे गिरफ्तार भी नहीं किया गया। इससे पुलिस की लाचारी साफ नजर आती है। इसके अलावा तत्कालीन प्रशिक्षु आईपीएस व तहसीलदार ने अभियुक्त के खिलाफ बयान दिए हैं। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त विधायक की रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया है।

मामले के अनुसार अकलेरा के तत्कालीन एसडीओ रामनिवास मेहता ने 5 फरवरी, 2005 को स्थानीय कलेक्टर को पत्र लिखा कि 3 फरवरी को मनोहर थाना के पास गांव के लोक खाताखेडी के उपसरपंच के चुनाव का रिपोल कराने को लेकर रास्ता रोक रहे थे। इस दौरान वह

और प्रशिक्षु आईपीएस सहित अन्य स्टाफ समझाइश कर रहा था। इतने में कंवरलाल अपने साथियों के साथ वहां आया और उसके सिर पर रिवाजस्वर लगाकर दोमिनट में रिपोल की घोषणा नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान उसने विभाग की ओर से कराई गई वीडियोग्राफी की कैसेट भी तोड़कर जला दी। घटना के समय दो थानाधिकारी व एक आरपीएस भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने विरोध नहीं किया। कलेक्टर की ओर से इस पत्र को

एसपी को भेजने के बाद 9 फरवरी को पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। वहीं बाद में निचली अदालत में आरोप पत्र पेश किया गया। एसीजेएम, मनोहर थाना ने 2 अप्रैल, 2018 को कंवरलाल को बरी कर दिया। इसके खिलाफ परिवादी और राज्य सरकार की अपील पर एंडीजे कोर्ट, अकलेरा ने 14 दिसंबर, 2020 को कंवरलाल को तीन साल की सजा के साथ 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। इसके खिलाफ पेश रिवीजन पर हाईकोर्ट ने 19 अक्टूबर, 2023 को सजा पर अंतरिम रोक लगा दी थी। इसके अलावा गत 17 अप्रैल को अदालत ने सभी पक्षों को सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

विधायकी रद्द करने की मांग

जयपुर। विधानसभा में अंता विधानसभा क्षेत्र से विधायक कंवर लाल मीणा को विरुद्ध एंजा लावाड द्वारा 3 वर्ष कारावास की सजा दिए जाने के फैसले पर राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित सजा के आदेश को यथावत रखा गया है।

राजस्थान प्रेस कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोट्यासरा तथा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जुली ने विधानसभा अध्यक्ष से मांग की है कि राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के पश्चात अंता विधानसभा क्षेत्र से चुने गए विधानसभा सदस्य कंवरलाल मीणा विधानसभा को सदस्यता के अयोग्य हो गए हैं

■ बाल विवाह की आशंका हो तो तुरंत चाइल्डलाइन 1098 या महिला हेल्पलाइन 181 पर जानकारी दें

करेगा। इस लांचन के साथ, राजस्थान सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि हर बच्चे को सुरक्षा, शिक्षा और सम्मान देना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अभियान के तहत सतर्क निगरानी, सामुदायिक भागीदारी और सरकार की त्वरित कार्रवाई को बढ़ावा दिया जाएगा।

अतिरिक्त मुख्य सचिव कुलदीप

रांका ने बताया कि राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और बाल अधिकार विभाग की ओर से नागरिकों से अपील की गई है कि यदि कहीं बाल विवाह की आशंका हो तो तुरंत चाइल्डलाइन 1098 या महिला हेल्पलाइन 181 पर जानकारी दें।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान राज्य

‘ग्राम सिरोली में विकसित होगी आवासीय योजना’

जयपुर। जयपुर के तहसील सांगानेर के सिरोली गाँव में राजस्थान आवासन मंडल आवासीय योजना विकसित करेगा। नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव एवं मण्डल अध्यक्ष श्री वैभव गालरिया ने बताया कि राजस्थान आवासन मंडल राजस्थान सरकार की मंशानुसार आमजन के अपने आवास के सपने को साकार करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में सांगानेर के सिरोली में 329.17 हेक्टेयर भूमि पर आवासन मंडल द्वारा आवासीय योजना विकसित की जाएगी।

सिविल लाइंस कूच करने के प्रयास में बेनीवाल समर्थकों सहित हिरासत में



पुलिस ने हनुमान बेनीवाल और उनके समर्थकों को शुक्रवार को हिरासत में ले लिया और सांगानेर सदर थाने ले गई।

सात दिन से धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। उन्होंने कहा, एसओजी की जांच में सामने आया है कि 400 से ज्यादा एसआई फर्जी तरीके से चयनित हुए हैं। इस भर्ती को रद्द करवाने की मांग को लेकर युवा लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार

चुप है। उन्होंने इस पूरे मामले में भाजपा-कांग्रेस पर मिले होने का आरोप लगाते हुए कहा, कि अपनी सरकार के समय सचिन पायलट ने युवाओं को न्याय दिलाने के लिए पैदल यात्रा निकाली थी, लेकिन अब वे इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने मंत्री डॉ किरोड़ीलाल मीना को लेकर

कहा कि वे मंत्री बनने के बाद युवाओं की आवाज नहीं उठा पा रहे। हनुमान बेनीवाल को पुलिस द्वारा हिरासत में लेने के बाद एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे बेरोजगार और बेनीवाल समर्थक वापस सहीद स्मारक पर इकठ्ठा हुए और धरना जारी रखा।

आमजन को हीट वेव से राहत देने के लिए चिकित्सा विभाग अपनी पूरी तैयारी रखे

मुख्यमंत्री भजनलाल ने चिकित्सा विभाग की समीक्षा बैठक में कड़े निर्देश दिये

जयपुर, 2 मई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि लू–तापघात (हीट वेव) और गर्मी जनित अन्य बीमारियों से आमजन को राहत पहुंचाने के लिए चिकित्सा विभाग अपनी पूरी तैयारी रखे और जिला कलक्टर नियमित तौर पर अस्पतालों का निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी अस्पताल एवं स्वास्थ्य केंद्रों का पूर्ण रख–रखाव किया जाए एवं किसी भी तरह की कमी पाए जाने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। शर्मा ने कहा कि गर्मी के मौसम में आमजन को बिजली, पानी एवं चिकित्सकीय सुविधाओं की निरंतर उपलब्धता राज्य सरकार की प्राथमिकता है। अधिकारी संवेदनशीलता के साथ पूरे समर्पण भाव से काम करें, जिससे लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

मुख्यमंत्री शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना के तहत प्रत्येक जिले में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को विकसित कर आत्मनिर्भर बनाया जाए तथा स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाते हुए महामारियों से बचाव के लिए उच्च स्तर की तैयारियों को जाएं।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में लू से निपटने की तैयारियों के मद्देनजर अस्पतालों में दवाइयां और उपकरणों की हर समय उपलब्धता हो। हीट वेव की स्थिति में नियमित निगरानी



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि लू-तापघात और गर्मी जनित अन्य बीमारियों से आमजन को राहत पहुंचाने के लिए पूरी तैयारी रखें।

रखी जाए तथा चिकित्सालयों में हर समय सभी आवश्यक मेडिकल

व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में

- मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला कलैक्टर नियमित तौर पर अस्पतालों का निरीक्षण करें। किसी भी प्रकार की कमी पाये जाने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्यवाही की जाए।**

संचालित सभी आयुष्मान आरोग्य मन्दिरों में इस वर्ष तक प्रमुख 12 सेवाएं मिलना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने एम्बुलेंस सेवाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि इन्हें अत्याधुनिक चिकित्सकीय सुविधाओं से लैस करते हुए इनकी नियमित मॉनिटरिंग की जाए। साथ ही, एम्बुलेंस की संख्या में भी बढ़ोतरी की जाए। शर्मा ने कहा कि राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत प्रदेशवासियों का स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटल रूप से संधारित करने के लिए प्रदेश के हर व्यक्ति की न केवल आभा आईडी बनाई जाए, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि आभा आईडी का अधिक से अधिक उपयोग शीघ्र प्रारम्भ हो।

इस दौरान, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ने विभाग की योजनाओं, कार्यक्रमों एवं नवाचारों का प्रस्तुतिकरण दिया। बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवरपर सहित, वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद थे।

एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी नए उप वायु सेना प्रमुख

नई दिल्ली, 02 मई। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी ने शुक्रवार को नए उप वायु सेना प्रमुख का कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने एयर मार्शल एस.पी. धरकर का स्थान लिया है, जो 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हुए। कार्यभार संभालने से पहले एयर मार्शल तिवारी गांधीनगर स्थित दक्षिण–

- उन्हें 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हुए एयर मार्शल एस.पी. धारकर की जगह नियुक्त किया गया है।**

पश्चिमी वायु कमान (एसडब्ल्यूएसी) के एयर ऑफिसर कमांडिंग–इन–चीफ की योजनाओं, कार्यक्रमों एवं नवाचारों के रूप में तैनात थे। वायु सेना मुख्यालय ‘वायु पवन’ में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।

भारतीय वायु सेना ने एक्स पर जानकारी देते हुए कहा, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, और वायु सेना मेडल से सम्मानित एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी ने 2 मई 2025 को उप वायु सेना प्रमुख का पदभार संभाल लिया है।

पाक प्रधानमंत्री का यू ट्यूब अकाउण्ट भारत में बैन

नई दिल्ली, 02 मई। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के आधिकारिक यूट्यूब चैनल को भारत में ब्लॉक कर दिया। चैनल पर अब यह संदेश दिख रहा है– ‘यहां सामग्री राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े सरकारी आदेशों के कारण इस देश में उपलब्ध नहीं है।’ शहबाज शरीफ का चैनल अब तक का सबसे हाई–प्रोफाइल खाता है, जिसे भारत सरकार ने ब्लॉक किया है। इससे

श्रीनगर के हिन्दू परिवार को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी

पहलगाम हमले के बाद श्रीनगर के उक्त हिन्दू परिवार को पाकिस्तान निर्वासित किये जाने की तैयारी है

नयी दिल्ली, 02 मई। उच्चतम न्यायालय ने जम्मू–कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान निर्वासन के खतरे का सामना कर रहे श्रीनगर के एक परिवार को शुक्रवार को अंतरिम राहत दी।

न्यायमूर्ति एन के सिंह की पीठ ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे उस परिवार के खिलाफ सिविल न्याय सहित कोई भी बलपूर्वक कार्रवाई न करें, जब तक कि उनके भारतीय राष्ट्रियता के दावों की पुष्टि करने के बाद कोई निर्णय न हो जाए।

पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकवादी हमले में कम से कम 26 लोग मारे गए थे। इस कूर घटना

के बाद के बाद श्रीनगर का एक विवाहित जोड़ा और उनके चार बच्चों पर निर्वासन का खतरा मंडरा रहा है।

परिवार ने अदालत के समक्ष दलील दी है कि वे भारतीय नागरिक हैं और उनके पास आधार कार्ड, वैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और भारतीय पासपोर्ट जैसे वैध सरकारी पहचान पत्र हैं।

पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया। इस वजह से भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं निलंबित कर दीं और सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 27 अप्रैल तक देश छोड़ने का आदेश दिया।

याचिकाकर्ता–परिवार ने आरोप लगाया कि उन्हें अन्यायपूर्ण तरीके से

भाखड़ा बांध से हरियाणा को 8 दिन तक अतिरिक्त पानी मिलेगा

नई दिल्ली, 02 मई। केन्द्र सरकार ने हरियाणा की पानी की जरूरतों को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। केन्द्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में सलाह दी गई कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) का फैसला लागू किया जाए। इसके तहत, अगले

- केन्द्रीय गृह सचिव के साथ बैठक में किए गए फैसले के तहत 4500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी दिया जाएगा।**

आठ दिनों तक भाखड़ा डैम से हरियाणा को 4,500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ा जाएगा। सरकारी प्रेस विज्ञप्त के मुताबिक, बैठक में यह भी तय हुआ कि डैम भरने के दौरान पंजाब को भी जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त पानी दिया जाएगा।

इस बैठक में केन्द्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के प्रतिनिधि और बीबीएमबी के अफसर शामिल हुए।

इस बैठक का मकसद था, हरियाणा और राजस्थान के कुछ इलाकों की पानी की तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त पानी छोड़ने के फैसले को अमल में लाना। बीबीएमबी जट्ट ह्री अपने बोर्ड की बैठक बुलाएगा, जिसमें पानी छोड़ने के तरीके और समय को लेकर रूपरेखा तैयार की जाएगी।

भाखड़ा और पोंग डैम से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की पानी की जरूरतें पूरी होती हैं। बीबीएमबी हर साल 21 मई से अगले साल 21 मई तक के लिए इन राज्यों का पानी की कोटा तय करता है।

पाक अधिकृत कश्मीर के 1००० मदरसे बंद

समझा जाता है कि भारतीय सेना के हमले की आशंका में यह कदम उठाया गया है

इस्लामाबाद, ०2 मई। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में 1०00 से अधिक मदरसे कम से कम 1० दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं। स्थानीय अधिकारियों ने शुक्रवार को यह घोषणा की। विश्वसनीय स्रोतों ने बताया कि भारत की तरफ से हमले के डर की वजह से पीओके में स्थित मदरसों को बंद कर दिया गया।

भारत यह दावा करता रहा है कि इन संस्थानों का इस्तेमाल आतंकवादियों के छिपने के ठिकाने के रूप में किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि भारत पाकिस्तान के साथ पूर्ण पैमाने पर युद्ध शुरू नहीं करेगा, लेकिन नियंत्रण रेखा (एलओसी) के साथ पीओके क्षेत्रों में कुछ हमले जरूर करेगा। 29 सितंबर 2०16 को, भारतीय सेना के कर्मांडो की टीमों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में प्रवेश कर आतंकी ठिकानों में

केन्द्रीय मंत्री रिजीजू भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष लेकर वियतनाम पहुंचे

ये पवित्र अवशेष वेसाक दिवस स्मरणोत्सव के रुप में 2 मई से 21 मई तक वियतनाम के विभिन्न भागों में प्रदर्शित किए जाएंगे

नयी दिल्ली/ हो चीमिन् सिति, 02 मई। भारत और वियतनाम के बीच सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उपलब्धि के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण आदान–प्रदान के अंतर्गत केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, आंध्र प्रदेश के मंत्री कंदुला दुर्गेश, मिश्रुओं और अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल साथ भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष वियतनाम की राजधानी हो ची मिन्ह शहर पहुंचे है।

ये पवित्र अवशेष 02 मई से 21 मई तक वेसाक दिवस स्मरणोत्सव के भाग के रूप में वियतनाम में लोगों के दर्शन के लिए विभिन्न पवित्र स्थलों पर रखे जाएंगे। संस्कृति मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार रिजिजू ने इस अवसर पर आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भारत के लोगों की ओर से एक सार्थक संदेश दिया। उन्होंने वियतनाम बौद्ध

विश्वविद्यालय में भारत से लाए गए पवित्र बोधि वृक्ष का पौधा भी लगाया। इस अवसर पर औपचारिक प्रार्थना के बाद अवशेषों को थान टैम मठ में स्थापित किया गया।

सारनाथ से भगवान बुद्ध के इन पवित्र अवशेषों को आज एक विशेष विमान द्वारा हो ची मिन्ह सिटी पहुंचाया गया। इसके साथ ही वियतनाम में 06 से 08 मई तक मनाए जाने वाले संयुक्त राष्ट्र वेसाक दिवस समारोह की तैयारियों का शुभारंभ हो गया है। इन अवशेषों के आगमन पर वियतनाम सरकार और वियतनाम बौद्ध संघ ने आगमन पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, जो दोनों देशों को एकजुट करने वाले गहन और साझा आध्यात्मिक मूल्यों को प्रदर्शित करता है। पवित्र अवशेषों को औपचारिक प्रार्थना के बाद थान ताम मठ में श्रद्धापूर्वक स्थापित किया गया।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मामले में अदालती आदेश की पालना के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। प्रकरण में पांच सी टैंडर की जांच की जानी है, जिसमें समय लगने की संभावना है। इसलिए मामले में आठ

सप्ताह का समय दिया जाए। इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई आठ सप्ताह के लिए टाल दी है।

याचिका में अधिवक्ता पीसी भंडारी ने बताया कि साल 2०19 में डीओआईटी के तत्कालीन अधिकारी के

पवित्र अवशेषों को भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय और अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध परिसंघ के सहयोग से प्रदर्शित किया जा रहा है। इन्हें 07 मई तक हो ची मिन्ह शहर में जनता के लिए प्रदर्शित किया जाएगा, उसके बाद 21 मई तक ताई निन्ह, हनोई और हा नाम में प्रदर्शित किया जाएगा।

पवित्र अवशेषों को आज एक भव्य सार्वजनिक शोभा यात्रा के माध्यम से थान ताम पैगोडा लाया गया, जहाँ उन्हें सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखा जाएगा।

इस उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे समारोह के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जिसमें विशेष रूप से तैयार की गई प्रदर्शनी और भगवान बुद्ध के जीवन पर आधारित नृत्य–नाटिका शामिल है, जो भारत–वियतनाम बौद्ध विरासत की गहरी जड़ों को प्रदर्शित करता है।

‘हिमांशी तुम ...

उन्होंने हिमांशी के लिए पत्र लिखा और उसे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के सचिवालय को मेल किया गया। ललिताने कहा कि वे हिमांशी के करनाल के पते पर सीधे एक पत्र भेजेंगी। हिमांशी के शब्दों को दोहराते हुए ललिताने लिखा, “आपने कहा, हमें सिर्फ शांति चाहिए और निश्चित रूप से यह सही है। हम न्याय भी चाहते हैं।” ललिताने ने आगे लिखा, “आप स्पष्ट रूप से एक ऐसी महिला हैं जिसके विचार बिल्कुल स्पष्ट हैं कि वो क्या चाहती है और विनय जैसे नौसेना के जवान का आपसे ज्यादा साहसी। साथी कोई और नहीं है।”

आपने इस देश के हर विचारशील नागरिक के विचारों को दोहराया है। और हम सबको, प्रेम व सद्भाव के आपके संदेश को दूर–दूर तक जाना चाहिए।”

गिरते पड़ते, ...

वाले एक ऐसे प्रमुख प्रोजेक्ट के रूप में रही है, जो वैश्विक व्यापार में भारत की स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा, लॉजिस्टिक क्षमता बढ़ायेगा तथा कार्गो ट्रांसशिपमेंट के लिये विदेशी बंदरगाहों पर निर्भरता को कम करेगा। विश्विन्नम पोर्ट को राष्ट्र को समर्पित करने के बाद, प्रधानमंत्री हेलिकॉप्टर से एयरपोर्ट पहुंचेंगे तथा फिर आंध्र प्रदेश जायेंगे।

राज्य सरकार ...

सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता प्रेमचंद देवदां ने बताया कि पिछली सुनवाई पर अदालत ने राज्य सरकार व चुनाव आयोग को पंचायत चुनाव का कार्यक्रम बताने का निर्देश दिया था, लेकिन इसके बाद भी राज्य सरकार व चुनाव आयोग ने अभी तक पंचायत चुनाव कार्यक्रम पेश नहीं किया है।

राज्य सरकार व चुनाव आयोग की ओर से लगातार अदालती निर्देशों की अवहेलना की जा रही है। इस पर राज्य सरकार ने कहा कि उन्होंने जवाब पेश कर दिया है। इसमें कहा है कि पंचायत पुनर्गठन एवं परिसीमन के बाद ही चुनाव कराए जाएंगे। वही, अदालत ने नगर पालिकाओं के चुनाव मामले में भी नोटिस जारी किए हैं। इसलिए यह मामला भी नगर पालिका चुनाव मामले में दायर याचिका के साथ ही सूचीबद्ध किया जाए।

राज्य सरकार के इस जवाब पर याचिकाकर्ता ने आपत्ति जताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के साल 2022 में दिए गए आदेश में स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार व चुनाव आयोग, पंचायत पुनर्गठन और परिसीमन के कारण पंचायत चुनाव को स्थगित नहीं कर सकते।

समय पर चुनाव कराया जाना चुनाव आयोग की ज़िम्मेदारी है। नगर पालिका चुनाव का मामला अलग और नया है, जबकि पंचायत चुनाव वाले मामले में अदालत राज्य सरकार व चुनाव आयोग से चुनाव कार्यक्रम मांग चुकी है। याचिका पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने चुनाव आयोग से जवाब मांगते हुए मामले की सुनवाई 30 मई को तय की है।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, जी–1–2०1, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौन सिटी, जिला करौली से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक–राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. **RAJHIN/2008/27147** जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333–34, फैक्स : 0141–2373513, कोटा कार्यालय : पालपाया हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744–2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हट्या, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151–2527371, वदयपुर कार्यालय: आचड़ मैन रोड आचड़, वदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294–2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रतू भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेरा फोन: 2627612, फैक्स:0145–2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रियल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973–226424 चूरू कार्यालय : एच–150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562–256908

